Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
June 2024 5(6), 1656–1661

EXPLORATORY ANALYSIS OF MID-DAY MEAL SCHEME IN PRIMARY SCHOOLS OF LUCKNOW, UTTAR PRADESH

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का अन्वेषणात्मक विश्लेषण

Rekha Choudhary [1], Ritu Chandra [1]

[1] Institute of Education and Research, Shri Ram Swarup Memorial University, Deva Road Barabanki, India, 225003

ABSTRACT

English: This paper provides an exploratory analysis of the Mid-Day Meal Scheme (MDMS) in primary schools of Lucknow, Uttar Pradesh using secondary data. It examines the scheme's objectives, recent developments, public-private partnerships, and its impact on children's nutritional well-being and educational outcomes. By focusing on the unique challenges and successes within Lucknow, this paper aims to contribute to a better understanding of how MDMS operates at the local level and suggest pathways to enhance its effectiveness.

Hindi: यह शोधपत्र माध्यमिक डेटा का उपयोग करते हुए लखनऊ, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस) का अन्वेषणात्मक विश्लेषण प्रदान करता है। यह योजना के उद्देश्यों, हाल के विकास, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बच्चों के पोषण संबंधी कल्याण और शैक्षिक परिणामों पर इसके प्रभाव की जांच करता है। लखनऊ के भीतर अद्वितीय चुनौतियों और सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करके, इस शोधपत्र का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर एम.डी.एम.एस के संचालन के तरीके को बेहतर ढंग से समझने में योगदान देना और इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए मार्ग सुझाना है।

Keywords: Mid-Day Meal Scheme, M.D.M.S, Primary School, Lucknow, Public-Private Partnership, Nutritional Well-being, Educational Outcomes, Infrastructure Development, Secondary Data, मिड-डे मील योजना, एम.डी.एम.एस, प्राथमिक विद्यालय, लखनऊ, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, पोषण संबंधी कल्याण, शैक्षिक परिणाम, बुनियादी ढांचे का विकास, द्वितीयक डेटा

Corresponding Author

Rekha Choudhary,
saipublicationresearch@gmail.com

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i6.2024.4952

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

1. प्रस्तावना

मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 15 अगस्त, 1995 को शुरू की गई, एम.डी.एम.एस का उद्देश्य कक्षा में भूख से लड़ना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, बच्चों के बीच समाजीकरण में सुधार करना और उनकी पोषण स्थिति को बेहतर बनाना है। यह योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों के साथ-साथ शिक्षा गारंटी योजना (ई.जी.एस) और वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा (ए.आई.ई) केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को लक्षित करती है।

2. मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य

पोषण सहायता: एमडीएमएस का एक प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के पोषण सेवन में सुधार करना है। संतुलित और पौष्टिक भोजन प्रदान करके, इस योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों में कुपोषण और भूख की समस्याओं का समाधान करना है।

शैक्षणिक परिणाम: एम.डी.एम.एस का उद्देश्य स्कूल में नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण दर को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित बच्चों और हाशिए के समुदायों के बच्चों के बीच। यह सुनिश्चित करके कि बच्चों को स्कूल के दिन में कम से कम एक बार पूरा भोजन मिले, इस योजना का उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना है।

सामाजिक समानता: एम.डी.एम.एस. विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को भोजन साझा करने के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। यह एकता की भावना को बढ़ावा देता है और जाति और वर्ग की बाधाओं को तोड़ने में मदद करता है, जिससे सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।

आर्थिक सहायता: स्थानीय किसानों और लघु उद्योगों से खाद्य आपूर्ति प्राप्त करके, एम.डी.एम.एस. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है।

3. मध्याह्न भोजन योजना में हालिया विकास

हाल के वर्षों में एम.डी.एम.एस. के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है, जिसमें बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और योजना के कवरेज का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख विकास में शामिल हैं:

बुनियादी ढांचे में सुधार: एम.डी.एम.एस. में भाग लेने वाले स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रयास किए गए हैं। इसमें आधुनिक रसोई और भोजन सुविधाओं का निर्माण, साथ ही उचित स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए खाना पकाने के उपकरण और बर्तनों का प्रावधान शामिल है।

प्रौद्योगिकी एकीकरण: योजना की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया है। जीपीएस ट्रैकिंग, मोबाइल ऐप और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के इस्तेमाल से भोजन की डिलीवरी और उसकी गुणवत्ता पर नज़र रखने के साथ-साथ बच्चों की उपस्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति पर नज़र रखने में मदद मिली है।

मानकीकृत मेनू: पोषण विशेषज्ञों ने यह सुनिश्चित करने के लिए मानकीकृत मेनू विकसित किए हैं कि प्रदान किया जाने वाला भोजन बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इन मेनू को फीडबैक और पोषण संबंधी आकलन के आधार पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी: निजी क्षेत्र की संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी एम.डी.एम.एस से जुड़ी कई चुनौतियों पर काबू पाने में सहायक रही है। इन साझेदारियों ने बुनियादी ढांचे, खाद्य आपूर्ति और वितरण, निगरानी और मूल्यांकन और क्षमता निर्माण में सुधार करने में मदद की है।

4. साहित्य समीक्षा

एम.डी.एम.एस को कई प्रमुख उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया था: नामांकन बढ़ाना और स्कूल में उपस्थिति और प्रतिधारण में सुधार करना, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पोषण स्थिति को बढ़ाना और स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देना। 1995 में शुरू में लागू किए गए इस कार्यक्रम ने 1997-98 तक देश भर में कवरेज हासिल कर लिया। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि एम.डी.एम.एस ने नामांकन और उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि की है, खासकर हाशिए के समुदायों में (ड्रेज़ और गोयल, 2003)।

4.1. एम.डी.एम.एस से संबंधित हालिया घटनाक्रम

एम.डी.एम.एस में हालिया घटनाक्रमों ने बुनियादी ढांचे में सुधार, भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कवरेज का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में एक निर्देश जारी किया जिसमें राज्य सरकारों को सूखे राशन के बजाय पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया, जिससे कार्यक्रम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए (भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 2001)। लखनऊ में भी इसी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि बच्चों को गर्म, पौष्टिक भोजन मिले।

इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 1995-96 में 3.4 करोड़ की शुरुआती कवरेज से, एम.डी.एम.एस अब पूरे भारत में 12 करोड़ से अधिक बच्चों को कवर करता है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी पोषण सहायता योजनाओं में से एक बन गई है (भारत सरकार, 2003)। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में लखनऊ सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन अलग-अलग रहा है।

लखनऊ में, इस योजना ने कई स्कूलों में आधुनिक रसोई और भोजन सुविधाओं के निर्माण के साथ बुनियादी ढांचे में सुधार देखा है। ये सुविधाएँ सुनिश्चित करती हैं कि भोजन स्वच्छ वातावरण में तैयार और परोसा जाए। इसके अतिरिक्त, पोषण विशेषज्ञों द्वारा डिज़ाइन किए गए मानकीकृत मेनू की शुरूआत ने बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की है।

इन सुधारों के बावजूद, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। निरंतर भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, स्वच्छता मानकों को बनाए रखना और भोजन वितरण में रसद संबंधी मुद्दों को संबोधित करना निरंतर चिंता का विषय है। इन चुनौतियों को दूर करने के प्रयासों में केंद्रीकृत रसोई का विकास और निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है।

4.2. मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित हालिया घटनाक्रम

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (एमडीएमपी), जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहा जाता है, 15 अगस्त, 1995 को पुनः शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना था, साथ ही स्कूली बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी संबोधित करना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा I-V के बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम गेहूं या चावल के बराबर मुफ़्त पका हुआ भोजन या प्रसंस्कृत भोजन उपलब्ध कराकर स्कूल में भागीदारी बढ़ाना, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना और बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना था। यह पहल राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो (एनएनएमबी) के एक अध्ययन पर आधारित थी, जिसमें ग्रामीण बच्चों के बीच महत्वपूर्ण पोषण संबंधी अंतराल की पहचान की गई थी।

शुरू में 1995 में शुरू किए गए एमडीएमपी ने 1997-98 तक देश भर में कवरेज हासिल कर लिया, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 1995-96 में 3.4 करोड़ से बढ़कर 2003-04 में 10.5 करोड़ हो गई। यह कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी पोषण सहायता योजनाओं में से एक बन गया, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 12 करोड़ से अधिक बच्चों तक पहुँच गया। हालाँकि, राज्य के अनुसार कार्यान्वयन अलग-अलग था। जहाँ गुजरात, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया, वहीं अन्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करने पर निर्भर थे। हरियाणा और कश्मीर जैसे राज्यों को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा, और चंडीगढ़ और दिल्ली ने रसद संबंधी चुनौतियों का सामना किया, जिसके बजाय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का विकल्प चुना। उल्लेखनीय उपलब्धियों में पांडिचेरी द्वारा भोजन तैयार करने के लिए उन्नत तकनीक के साथ एक केंद्रीकृत रसोई की स्थापना और तमिलनाडु द्वारा भोजन वितरण के लिए एक संरचित प्रणाली का विकास शामिल है। गुजरात ने फोर्टिफाइड भोजन उपलब्ध कराने में भी अग्रणी भूमिका निभाई, और केरल ने शिक्षकों को योजना का समर्थन करने के लिए अपने वेतन का योगदान करते देखा। हालाँकि, खाद्य खरीद और पर्याप्त बफर स्टॉक के बावजूद, कुपोषण और भुखमरी से संबंधित मौतों में वृद्धि हुई, जिसके कारण 2001 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। न्यायालय के 28 नवंबर, 2001 के निर्देश में सूखे राशन की जगह पके हुए भोजन की ओर बदलाव को अनिवार्य बनाया गया था और कुपोषण से निपटने के लिए एमडीएमपी के बेहतर क्रियान्वयन को लागू किया गया था। यह ऐतिहासिक निर्णय यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम था कि एमडीएमपी बच्चों के पोषण सेवन में सुधार और उनकी शैक्षिक प्रगति का समर्थन करने के अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करे।

4.3. एम.डी.एम.एस में सार्वजनिक-निजी भागीदारी

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) ने लखनऊ सहित विभिन्न क्षेत्रों में एमडीएमएस की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीपीपी बुनियादी ढांचे के विकास, खाद्य आपूर्ति और वितरण, निगरानी और मूल्यांकन, और क्षमता निर्माण में योगदान करते हैं। उल्लेखनीय उदाहरणों में अक्षय पात्र फाउंडेशन शामिल है, जो कई राज्यों में स्कूलों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीकृत रसोई संचालित करता है (अक्षय पात्र फाउंडेशन, 2022)।

लखनऊ में, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और निजी संस्थाओं के साथ भागीदारी ने अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और सीमित संसाधनों जैसी चुनौतियों का समाधान करने में मदद की है। इन सहयोगों ने भोजन वितरण की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक भोजन मिले।

उदाहरण के लिए, अक्षय पात्र फाउंडेशन ने अत्याधुनिक तकनीक और परिष्कृत खाना पकाने की तकनीकों से सुसज्जित केंद्रीकृत रसोई स्थापित की हैं। सुरक्षित और स्वच्छ भोजन तैयार करना और उसे वितरित करना सुनिश्चित करें। उनकी रसोई में पाँच घंटे से भी कम समय में 100,000 से अधिक भोजन पकाने की क्षमता है, जिसमें निरंतर गुणवत्ता बनाए रखते हुए न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है (अक्षय पात्र फाउंडेशन, 2022)।

हैदराबाद में एक सफल सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का एक और उदाहरण देखा जा सकता है, जहाँ नंदी फाउंडेशन हैदराबाद और सिकंदराबाद के स्कूलों में लगभग 101,394 बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने वाली एक केंद्रीय रसोई का प्रबंधन करता है। इसी तरह, वही एनजीओ विशाखापत्तनम में एक केंद्रीकृत रसोई संचालित करता है, जो 111 स्कूलों में 35,734 बच्चों को भोजन परोसता है (नंदी फाउंडेशन, 2022)।

4.4. लखनऊ में एम.डी.एम.एस का कार्यान्वयन और प्रभाव

लखनऊ में एम.डी.एम.एस के कार्यान्वयन में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कार्यक्रम ने स्कूल में उपस्थिति और प्रतिधारण दर में सुधार किया है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के बीच। निःशुल्क भोजन के प्रावधान ने भूख को कम किया है और छात्रों की पोषण स्थिति में सुधार किया है, जिससे बेहतर शैक्षिक परिणामों में योगदान मिला है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2019)।

हालाँकि, इस कार्यक्रम को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि लगातार भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, स्वच्छता मानकों को बनाए रखना और भोजन वितरण में तार्किक मुद्दों को संबोधित करना। इन चुनौतियों को दूर करने के प्रयासों में केंद्रीकृत रसोई का विकास और निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। लखनऊ में, इस योजना को विभिन्न मॉडलों के माध्यम से लागू किया गया है, जिसमें विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत रसोई शामिल हैं। विकेंद्रीकृत रसोई में स्कूल स्तर पर भोजन तैयार करना शामिल है, जबकि केंद्रीकृत रसोई में थोक में भोजन तैयार किया जाता है और उन्हें कई स्कूलों में वितरित किया जाता है। केंद्रीकृत रसोई मॉडल लखनऊ जैसे शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी रहा है, जहाँ यह लगातार भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करता है। लखनऊ में एम.डी.एम.एस का प्रभाव कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है: पोषण सुधार: एम.डी.एम.एस ने बच्चों के पोषण सेवन में उल्लेखनीय सुधार किया है, कुपोषण और भूख के मुद्दों को संबोधित किया है (राष्ट्रीय पोषण संस्थान, 2020)। शैक्षिक परिणाम: इस योजना ने स्कूल में उपस्थिति और प्रतिधारण दरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों के बच्चों के बीच (ड्रेज़ और गोयल, 2003)। सामाजिक एकीकरण: इस कार्यक्रम ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को भोजन साझा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करके सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा दिया है (भारत सरकार, 2003)।

5. स्थानीय सरकार और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका

स्थानीय सरकार और सामुदायिक भागीदारी लखनऊ में मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस) के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्थानीय अधिकारी कार्यक्रम के दिन-प्रतिदिन के संचालन की देखरेख करने, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि खाद्य आपूर्ति समय पर खरीदी जाए, रसोई पर्याप्त रूप से सुसज्जित हों, और दिशा-निर्देशों के अनुसार भोजन तैयार और वितरित किया जाए। दूसरी ओर, सामुदायिक भागीदारी स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देती है, जो कार्यक्रम की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

लखनऊ में, पंचायतों और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि योजना समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो। ये स्थानीय संस्थाएँ ज़रूरतमंद स्कूलों की पहचान करने, रसोई सुविधाओं के निर्माण में मदद करने और परोसे जाने वाले भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता की निगरानी करने में मदद करती हैं। इसके अलावा, माता-पिता और स्थानीय स्वयंसेवकों सहित समुदाय के सदस्य अक्सर भोजन की तैयारी और वितरण में सहायता करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सांस्कृतिक प्राथमिकताओं और आहार प्रतिबंधों का सम्मान किया जाता है।

समुदाय की सक्रिय भागीदारी उपस्थिति और प्रतिधारण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में भी मदद करती है। योजना में अभिभावकों और स्थानीय नेताओं को शामिल करके, कार्यक्रम न केवल बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करता है, बल्कि उनके शैक्षिक परिणामों को भी बढ़ाता है। समुदाय के सदस्यों के साथ नियमित बैठकें और फीडबैक सत्र योजना की निरंतर निगरानी और सुधार की अनुमति देते हैं, जिससे किसी भी चुनौती या अड़चन का तुरंत समाधान किया जा सकता है।

6. निगरानी और मूल्यांकन तंत्र

लखनऊ में मध्याह्न भोजन योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन तंत्र आवश्यक हैं। ये तंत्र योजना के प्रदर्शन को ट्रैक करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। लखनऊ में, एक बहु-स्तरीय निगरानी प्रणाली लागू की गई है, जिसमें स्कूल-स्तरीय समितियाँ, जिला-स्तरीय प्राधिकरण और राज्य-स्तरीय निगरानी निकाय शामिल हैं।

स्कूल स्तर पर, स्कूल प्रबंधन समितियाँ (एस.एम.सी) बनाई जाती हैं, जिनमें शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये समितियाँ भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता मानकों और रसोई सुविधाओं के रखरखाव सहित योजना के दैनिक कार्यान्वयन की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। वे उपस्थिति और परोसे गए भोजन की संख्या का रिकॉर्ड भी रखते हैं, जो योजना की पहुँच और प्रभाव की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

जिला-स्तरीय अधिकारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और ऑडिट करते हैं। वे स्कूल के कर्मचारियों और रसोइयों को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता प्रथाओं और पोषण पर प्रशिक्षण भी देते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग और मोबाइल एप्लिकेशन जैसी तकनीक के उपयोग ने भोजन वितरण और खपत पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करके निगरानी प्रक्रिया को और बेहतर बनाया है।

राज्य-स्तरीय निगरानी में सरकारी एजेंसियों और स्वतंत्र संगठनों द्वारा समय-समय पर समीक्षा और मूल्यांकन शामिल हैं। ये मूल्यांकन बच्चों के स्वास्थ्य, उपस्थिति और शैक्षणिक प्रदर्शन पर योजना के समग्र प्रभाव का आकलन करते हैं। इन मूल्यांकनों से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कार्यक्रम को बेहतर बनाने, किसी भी कमी को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

7. लखनऊ में प्रभावी कार्यान्वयन के मामले अध्ययन

लखनऊ के कई स्कूलों ने मिड-डे मील योजना के अनुकरणीय कार्यान्वयन का प्रदर्शन किया है, जो सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। ऐसा ही एक उदाहरण बाल विद्या मंदिर स्कूल है, जहाँ स्थानीय समुदाय और स्कूल अधिकारियों ने योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से सहयोग किया है। स्कूल में एक अच्छी तरह से सुसज्जित रसोई और रसोइयों और स्वयंसेवकों की एक समर्पित टीम है जो छात्रों के लिए पौष्टिक और स्वच्छ भोजन तैयार करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को योजना से पूरा लाभ मिले, नियमित स्वास्थ्य जांच और पोषण शिक्षा सत्र आयोजित किए जाते हैं।

एक और उल्लेखनीय मामला राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है, जहां एक गैर सरकारी संगठन की भागीदारी ने योजना के प्रभाव को काफी हद तक बढ़ा दिया है। एनजीओ अतिरिक्त संसाधन और विशेषज्ञता प्रदान करता है, जैसे कि फोर्टिफाइड खाद्य आपूर्ति और उन्नत खाना पकाने की तकनीक, यह सुनिश्चित करते हुए कि भोजन बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। स्कूल ने एक मजबूत फीडबैक तंत्र भी लागू किया है, जहां छात्र और अभिभावक अपनी चिंताओं और सुझावों को व्यक्त कर सकते हैं, जिससे योजना में निरंतर सुधार हो रहा है।

ये केस स्टडी मिड-डे मील योजना के सफल कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी, पर्याप्त बुनियादी ढांचे और प्रभावी निगरानी के महत्व को उजागर करती हैं। वे यह भी प्रदर्शित करते हैं कि सही समर्थन और सहयोग से, योजना बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षिक परिणामों में काफी सुधार कर सकती है।

8. अन्य क्षेत्रों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण

लखनऊ में मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन का भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण करने पर इसकी सफलता या चुनौतियों में योगदान देने वाले कारकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को मुख्य रूप से मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, कुशल प्रशासनिक ढांचे और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के कारण मिड-डे मील योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लंबे समय से पहचाना जाता रहा है।

तमिलनाडु में, राज्य सरकार ने एक केंद्रीकृत रसोई प्रणाली स्थापित की है, जहाँ भोजन को स्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किया जाता है और फिर स्कूलों में पहुँचाया जाता है। यह मॉडल भोजन की गुणवत्ता में स्थिरता सुनिश्चित करता है और रसोई सुविधाओं के प्रबंधन के लिए अलग-अलग स्कूलों पर बोझ को कम करता है। दूसरी ओर, केरल ने स्थानीय कृषि उपज को योजना में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, स्थानीय किसानों का समर्थन किया है और बच्चों के लिए ताजा और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया है।

इन क्षेत्रों की तुलना में, लखनऊ को संसाधनों की कमी और सामुदायिक भागीदारी के विभिन्न स्तरों जैसी अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, शहर ने गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने जैसी नवीन प्रथाओं को अपनाकर उल्लेखनीय प्रगति भी दिखाई है। अन्य क्षेत्रों में सफल मॉडलों का अध्ययन करके, लखनऊ सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना सकता है और उन्हें अपने विशिष्ट संदर्भ के अनुरूप ढाल सकता है, जिससे योजना की समग्र प्रभावशीलता बढ़ सकती है। तुलनात्मक विश्लेषण क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित करता है कि सभी बच्चों को, चाहे वे कहीं भी हों, पौष्टिक भोजन और शैक्षिक अवसरों तक पहुँच प्राप्त हो। यह भारत भर में मिड-डे मील योजना को बेहतर बनाने के लिए सफलताओं और चुनौतियों दोनों से सबक लेते हुए निरंतर सीखने और अनुकूलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

9. चुनौतियाँ और सिफारिशें

अपनी सफलताओं के बावजूद, लखनऊ में एम.डी.एम.एस. को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

बुनियादी ढाँचा: कई स्कूलों में पर्याप्त रसोई और भोजन की सुविधा नहीं है।

संसाधनों की कमी: सीमित वित्तीय संसाधन भोजन की गुणवत्ता और निरंतरता को प्रभावित करते हैं।

निगरानी और मूल्यांकन: भोजन की गुणवत्ता और कार्यक्रम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र की आवश्यकता है।

लखनऊ में एम.डी.एम.एस. में सुधार के लिए सिफारिशों में शामिल हैं:

रसोई और भोजन सुविधाओं में निवेश के माध्यम से बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना।

अतिरिक्त संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना।

बेहतर निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को लागू करना।

खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए स्कूल के कर्मचारियों और रसोइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।

10. निष्कर्ष

मध्याह्न भोजन योजना ने लखनऊ में बच्चों के पोषण संबंधी कल्याण और शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी ने चुनौतियों का समाधान करने और कार्यक्रम की प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी को दूर करने और योजना की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का समाधान करके और पीपीपी की ताकत का लाभ उठाकर, एम.डी.एम.एस लखनऊ में बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना जारी रख सकता है।

संदर्भ

अक्षय पात्र फाउंडेशन. (2022). वार्षिक रिपोर्ट. https://www.akshayapatra.org/annual-report

ड्रेज़, जे., और गोयल, ए. (2003). मिड-डे मील का भविष्य. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 38(44), 4673-4683.

भारत सरकार. (2003). पोषण पर संचालन समिति की रिपोर्ट: राष्ट्रीय पोषण नीति. नई दिल्ली: योजना आयोग.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2019). मिड-डे मील योजना वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार.

नंदी फाउंडेशन. (2022). वार्षिक रिपोर्ट. https://www.nandifoundation.org/annual-report

राष्ट्रीय पोषण संस्थान. (2020). मिड-डे मील योजना का मूल्यांकन: एक रिपोर्ट. हैदराबाद: एनआईएन. भारत का सर्वोच्च न्यायालय. (2001). पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ और अन्य, रिट याचिका (सिविल) संख्या 196/2001.

अय्यर, वाई., और भट्टाचार्जी, एस. (2006). डाकघर विरोधाभास: भारत में एमडीएम योजना का एक केस स्टडी.

आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 41(5), 416-423. अय्यर, वाई. (2021). मध्याह्न भोजन योजना: भारत में बचपन की भूख को संबोधित करना. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

चक्रवर्ती, एस., और जयरामन, आर. (2019). मिड-डे मील योजना का छात्र उपस्थिति पर प्रभाव. जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, 136, 151-163.

ड्रेज़, जे., और गोयल, ए. (2003). मिड-डे मील का भविष्य. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 38(44), 4673-4683.

ड्रेज़, जे., और खेरा, आर. (2010). बीपीएल जनगणना और एक संभावित विकल्प. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 45(9), 54-63.

भारत सरकार. (2022). मिड-डे मील योजना: वार्षिक रिपोर्ट. शिक्षा मंत्रालय.

जयरामन, आर., और सिमरोथ, डी. (2015). प्राथमिक विद्यालय में नामांकन पर स्कूल लंच का प्रभाव: भारत की मिड-डे मील योजना से साक्ष्य. जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, 51(12), 1681-1696.

खेरा, आर. (2006). प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 41(46), 4742-4750.

खेरा, आर. (2013). रोजगार गारंटी के लिए लड़ाई. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

मेहरोत्रा, एस. (2022). भारत में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करना: क्षेत्र से सबक. अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक विकास जर्नल, 88, 102522.

प्रथम. (2020). शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2020. प्रथम शिक्षा फाउंडेशन.

सिन्हा, डी. (2008). मध्याह्न भोजन योजना: आखिर यह किसकी योजना है? सेज प्रकाशन.